Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.5442, Volume 08, No. 04, October, 2018, pp. 332-336

xkeh.k fodkl o –f"k vk/kkfjr m|kx

पूनम कँवर खँगारोत*

iLrkouk

राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 70% रोजगार की दृष्टि से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। राजस्थान में कृषि सिंचाई के कृत्रिम साधनों के अभाव में कृषक मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का दो तिहाई भाग खरीफ के मौसम में बोया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि का बोया गया क्षेत्र बाड़मेर में तथा सबसे कम राजसमंद जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ एवं बंजर भूमि जैसलमेर जिले में है। 1966–67 आर्थिक वर्ष में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था। हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग थे। राजस्थान में हरित क्रांति के तहत सर्वाधिक उत्पादन वृद्धि खाद्यान्न के क्षेत्र में हुई वर्तमान में राजस्थान अध्ययन की दृष्टि से आत्मनिर्भर राज्य है।

कृषि क्षेत्र के अन्य कार्यक्रम

श्वेत क्रांति	–	दुग्धोत्पादन
भूरी क्रांति	–	खाद्यान्न प्रसंस्करण
पीली क्रांति	–	तिलहन उत्पादन से संबंधित सर्वाधिक उत्पादन सरसों के क्षेत्र में हुआ
नीली क्रांति	–	मत्स्य उत्पादन से संबंधित
लाल क्रांति	–	टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित
गोल क्रांति	–	आलू उत्पादन से संबंधित
इंद्रधनुष क्रांति	–	सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु
रजत क्रांति	–	अण्डा उत्पादन

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सच्चा भारत गांवों में निवास करता है और इस देश की समृद्धि का मार्ग गांवों से होकर गुजरता है। इसका आशय यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास गांवों पर और गांवों की समृद्धि कृषि पर निर्भर है। अतः यदि कृषि उन्नत होती है तो स्वतः ही सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण भारत विकसित होता है। निःसन्देह कृषि विकास भारतीय अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण विकास के लिए एक रामबाण है। यह प्रेक्षण ब्रिटिश काल में जितना सही था उतना ही आज भी प्रामाणिक है। यद्यपि योजना काल में ग्रामीण एवं कृषि विकास के नाम पर प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में नये–नये संकल्प दोहराये गये, राष्ट–नीय पर्वो पर ग्रामीण एवं कृषि विकास की झांकियों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया, अनेक मेले एवं प्रदर्शनियां भी आयोजित की गई किन्तु परिणाम ले देकर वे ही ढाक के तीन पात रहे हैं। कृषि हमारे देश की प्राचीन परम्परा रही है। इसका अतीत अत्यन्त गौरवशाली रहा है। सम्मुन्नत कृषि के कारण ही यह देश यह देश 'सोने की चिडिया' और 'दूध दही की नदियां बहने वाले देश' के नाम से गौरवान्वित होता रहा है। देश की आध्यात्मिक एवं भौतिक क्षेत्र में

* रिसर्च स्कॉलर, अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा ज्योति राव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

प्रगति के पीछे कृषि ही सबसे बडी प्रेरक शक्ति रही है। वर्तमान में उन्नत कृषि तकनीकों का निर्यातक विकसित पश्चिमी विश्व जब घने जंगलों से ढका हुआ था और जब वहां सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का बीजारोपण भी नहीं हुआ था तब इस देश ने कृषि, उद्योग एवं व्यापारिक प्रगति के क्षेत्र में आसमानी ऊचाइयां प्राप्त कर ली थी। यदि यह माना जावे कि यह स्थिति 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध तक बनी रही तो भी कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इसके पश्चात् धीरे–धीरे गिरावट की प्रक्रिया आरम्भ हुई और यहां कि कृषि न केवल दूसरे देशों की तुलना में किन्तु अपने आप में भी पिछडने लगी। फलतः इस पर आधारित देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा गई। किन्तु फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक हम कृषि जन्य कच्चे माल एवं खाद्यान्न में न केवल स्वावलम्बी थे अपितु इनका विश्व बाजारों में निर्यात भी करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी क्षेत्रों में स्थितियां अनुकूल होनी चाहिए थी, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। राय निर्माताओं ने इसका दोशारोपण देश के विभाजन पर कर दिया। खैर, एक घटक यह भी रहा किन्तु मात्र इस ही कारण मानना समस्या की गम्भीरता की अनदेखी करना था।

1951 से योजानाबद्ध आर्थिक विकास की प्रक्रिया आरम्भ हो गई। पंचवर्षीय योजना यद्यपि कृषि प्रधान थी किन्तु वास्तव में इसमें कृषि विकास के लिए विशेष व्यूहरचना नहीं अपनाई गई। दूसरी योजना की प्राथमिकतायें बदलकर उसे उद्योग प्रधान बना दिया गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश अकालों की चपेट में आ गया। फलतः कृषि की स्थिति बंद से बदतर हो गई। देश में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। उदर पूर्ति के लिए भारी मात्रा में घटिया किस्म के गेहूँ एवं अन्य खाद्य पदार्थो का विदेशों से आयात करना पडा। देश की गौरवपूर्ण कृषि प्रधानता के मुंह पर यह एक करारा तमाचा था किन्तु इसे सहने के अलावा और कोई विकल्प नही रहा। कृषि विकास के सभी वायदे न केवल झूठे साबित हुए अपितु उनकी पोल भी खुल गयी। स्थिति से निपटने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना की गई। जिसे 'हरित क्रान्ति' का नाम दिया गया। हरित क्रान्ति की सफलतायें भी संदिग्ध है। यदि देश की लगभग 70 प्रतिषत जनसंख्या प्रकृति की अनुकूलताओं का सहारा पाकर जैसे तैसे देश को खाद्यानों में आत्मनिर्भरता और अपवाद स्वरूप खाद्यान के निर्यातक का सम्मान दिला देती है तो स्पष्ट है कि खतरा ज्यों का त्यों बना हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि देश का बहुत बडा भाग हरित क्रांति के लाभों से वंचित रहा है। जिन राज्यों में यह सफल रही वहां आर्थिक स्थिरता की स्थिति आ गई है और वहां का किसान कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना अपनाने के लिए व्याकुल है।

एक ओर कृषि को देश की विशाल जनसंख्या के लिए खाद्य सामग्री औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए कृषि जन्य कच्चे माल एवं विदेशी विनिमय जुटाने के लिए निर्यात योग्य अधिशेष की आपूर्ति के स्त्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृषि पैदावार बढ़ाना नितांत आवश्यक है ताकि सबको पर्याप्त भोजन मिले एवं कुपोषण से छुटकारा मिले, उद्योगों का पहिया घूमता रहे और विदेशी विनिमय की कमाई होती रहे। जबकि दूसरी ओर यदि किसान के श्रम को लागत में सम्मिलित कर लिया जाए तो कृषि आज भी लाभकारी व्यवसाय नहीं है। अतः कृषि में प्रवृत्ति के स्थान पर कृषि से निवृत्ति की लहर चल रही है। इस भावना ने भूमि के अनुकूलतम एवं कुशलता प्रयोग में बाधाएं उत्पन्न की हैं। यह कृषि की समस्या का परिणात्मक पक्ष है। इसका गुणात्मक पक्ष इससे भी गंभीर है अर्थात् कृषि उत्पादन में कुशलता अर्जित करने उसके भंडारण एवं वितरण की समुचित व्यवस्था करने की समस्याएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अतः कृषि विकास हेतु नए चिंतन एवं मंथन की आवश्यकता है।

सूती वस्त्र उद्योग

यह राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं सुसंगठित उद्योग है जो वर्तमान में भी राज्य का प्रमुख उद्योग है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना देशभक्त सेठ दामोदर दास ने ब्यावर नगर में की। यह राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। तत्पश्चात–

एडवर्ड्स मिल्स लिमिटेड	1906 में	द्वितीय
श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड	1925 में	ब्यावर में
मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स	1938 में	तृतीय भीलवाड़ा में
महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड	1942 में	पाली में
सार्दुल टेक्सटाइल्स लिमिटेड	1946 में	श्रीगंगानगर में
राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	1960 में	भीलवाड़ा में
आदित्य मिल्स		किशनगढ़ में
उदयपुर कॉटन मिल्स	1961 में	उदयपुर में
राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स	1968 में	भवानी मंडी में

राज्य में इस समय सुखी मिले निजी, सार्वजनिक एवं सहकारी तीनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं। **सार्वजनिक क्षेत्र की सूती मिलें** – यह निजी क्षेत्र में स्थापित मिलें थी, जिन्हें रुग्णता के कारण 1974 से राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। यह निम्न हैं –

- एडवर्ड मिल्स ब्यावर
- महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर
- श्री विजय कॉटन मिल्स (विजयनगर)

सहकारी क्षेत्र की कताई मिलें –	स्थापना वर्ष
राजस्थान सहकारी कताई मिल लि., गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)	1965
श्रीगंगानगर सहकारी कताई मिल लि., हनुमानगढ़	1978
गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड गंगापुर (भीलवाड़ा)	1981
1 अप्रैल, 1993 को इन तीनों मिलो एवं गुलाबपुरा की सहकारी जिनिंग मिल को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड की स्थापना की गई।	

राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल महाराजा उमेद मिल्स, पाली में है।

अन्य सूती वस्त्र मिलें

बांसवाड़ा फैब्रिक्स	बांसवाड़ा
आधुनिक पॉलिटेटेक्स	आबू रोड (सिरोही)
विजय कॉटन मिल्स	विजयनगर
मॉडर्न थ्रेड्स	रायला (भीलवाड़ा)
बांसवाड़ा सिंथेटिक्स	बांसवाड़ा
सुदर्शन टेक्सटाइल्स	कोटा
श्री गोयल इंडस्ट्रीज	कोटा
गंगापुर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल	गंगापुर

चीनी उद्योग

राजस्थान में सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ जिले में भोपाल सागर नगर में एक चीनी मिल दी मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से सन 1932 में प्रारंभ की गई। दूसरा कारखाना सन 1937 में श्री गंगानगर में दी गंगानगर शुगर मिल्स नाम से स्थापित हुआ। इसमें शक्कर बनाने का कार्य 1946 में प्रारंभ हुआ। 1956 में इस चीनी मिल को राज्य सरकार ने अधिग्रहित कर लिया तथा वह सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई। 1965 में बूंदी जिले के केशोरायपाटन में चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई। सन 1976 में उदयपुर में चीनी मिल निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। राजस्थान कुल कृषि भूमि के लगभग 10–16% पर गन्ने का उत्पादन करता है जो भारत के कुल उत्पादन का 1.11% है। संक्षिप्त में श्रीगंगानगर, भोपाल, सागर, उदयपुर व केशोरायपाटन में चीनी मिलें हैं। चुकंदर से चीनी बनाने के लिए श्री गंगापुर शुगर मिल्स लिमिटेड में एक योजना 1968 में आरंभ की गई थी। दी गंगापुर शुगर मिल्स शराब बनाने का कार्य भी करती है जिसके केंद्र अजमेर, अटरू, प्रतापगढ़ तथा जोधपुर में हैं।

रासायनिक उद्योग

डीडवाना में 1964 में स्थापित राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा सोडियम सल्फेट का कारखाना। इसकी स्थापना कृत्रिम रूप से कागज तैयार करने में काम आने वाले लवण के उत्पादन हेतु की गई है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक उपक्रम –

राजस्थान सरकार द्वारा चार प्रकार के सार्वजनिक उपक्रम संचालित किए जा रहे हैं :

वैधानिक बोर्ड निगम (Statutory Boards Corporations): इस श्रेणी में वे उपक्रम आते हैं जिन की स्थापना राज्य विधानसभा द्वारा पृथक से पारित किए गए अधिनियम के तहत होती है। इस श्रेणी में निम्न उपक्रम संचालित हैं –

- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC): राज्य में नागरिकों को पथ परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1964 में स्थापित
- राजस्थान वित्त निगम (RFC): उद्योगों को वित्त सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 1955 में स्थापित।
- राजस्थान आवासन मंडल (RHB): लोगों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 1970 में गठित।
- राजस्थान राज्य भंडारण निगम (RSWC): राज्य के कृषकों को कृषि आदानों एवं उपजो के भंडारण की सुविधाएं तथा गोदाम भंडार गृह आदि उपलब्ध कराने हेतु 1957 में स्थापित।
- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (RSAMB): यह बोर्ड प्रदेश में कृषि उत्पादों के विपणन हेतु मंडिया स्थापित करने एवं उनका संचालन करने तथा मंडी सड़कों पर निर्माण के उद्देश्य से 1974 में गठित किया गया।

diuh vf/kfu;e 1956 d rgr i th—r difu;k

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (RSMML): इसमें 20 फरवरी 2003, को RSMDC का विलय कर दिया गया है। अतः अब RSMDC का अस्तित्व समाप्त हो गया है।

- राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लि.
- राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लि.
- कोटा में श्रीराम फर्टिलाइजर्स कारखाना तथा देबारी के जिंक सेमेल्टर से रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है।
- खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है।
- खाद बनाने हेतु एक संयंत्र की स्थापना गडेपान कोटा में की गई है।

राजस्थान में इंजीनियरिंग कारखाने

इंजीनियरिंग उद्योग 1943 में (प्रथम बार) जयपुर मेटल की स्थापना हुई।

कैप्सन मीटर कंपनी	जयपुर व पाली (पानी के मीटर बनते हैं)
जयपुर मेटल्स	जयपुर (बिजली के मीटर)
इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	कोटा (मशीनों व यंत्रों का उत्पादन)
मान इंडस्ट्रियल कारपोरेशन	जयपुर (लोहे के टॉवर तथा इमारती खिड़कियां आदि)
केबल इंडस्ट्री	कोटा व पिपलिया में
सिमको वैगन फैक्ट्री	भरतपुर रेल के डिब्बे
नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी	जयपुर, जो विभिन्न प्रकार के बियरिंग बनाती है और इस क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है।
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन	जयपुर (टी. वी.)
फ्लोर्सपार संयंत्र डूंगरपुर	यहां इस्पात, एलुमिनियम व फ्लोराइड बनाने के लिए फ्लोर्सपार तैयार किया जाता है।
कृत्रिम रेशम के कारखाने	कोटा, गुलाबपुरा, जयपुर, बांसवाड़ा
टायर उद्योग	कोटा, कांकरोली
माचिस के कारखाने	अलवर, कोटा, उदयपुर, फतेहगढ़

खेलकूद सामान	हनुमानगढ़
एलॉय स्टील	उदयपुर, जयपुर
बड़ी लाइन के वैगन	वैगन फैक्ट्री, कोटा
इंजनों की मरम्मत तथा मालगाड़ी के डिब्बे	लोको एंड कैरिज वर्कशॉप, अजमेर
सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट	अलवर
हिंदुस्तान मशीन टूल्स	अजमेर
राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज	भिवाड़ी
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड	देवारी, उदयपुर
जामेटिया पेपर मिल्स	भीलवाड़ा
लेलैंड ट्रक्स कारखाना	अलवर
अवंति स्कूटर्स	अलवर
ओरिएंटल पावर केबल्स	कोटा

संदर्भ में निम्नांकित सुझाव विचारणीय हैं

सरकार की ओर से एकमुश्त कृषि नीति की घोषणा आज भी अपेक्षित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो कुछ भी हुआ है वह परिस्थितिजन्य एवं टुकड़ों में हुआ है तथा इनका निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों ही दोषपूर्ण रहे हैं। अतः किसानों, कृषि विशेषज्ञों, शोध संस्थानों एवं ग्रामीण अर्थशास्त्रियों के सहयोग से यथाशीघ्र देश की कृषि नीति का निर्माण किया जाए और किसी निष्पक्ष संस्था द्वारा इस नीति को लागू करने से पूर्व रायशुमारी करवाई जाए। कृषि विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों एवं ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में आए बुद्धिजीवियों एवं शिक्षविदों को इस कृषि नीति के क्रियान्वयन की समय–समय पर समीक्षा करनी चाहिए और विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा सरकार को अपने विचारों एवं सुझावों से अवगत कराना चाहिए। कृषि तकनीकों एवं अनुसंधान का भारतीय किसान को हस्तांतरण बहुत धीमा एवं दोषपूर्ण रहा है। अतः उसकी तकनीक को एवं अनुसंधानों को ग्रहण करने की सामर्थ्य का सदुपयोग किया जाए। राष्ट्रीय टेलीविजन कार्यक्रमों एवं प्रौढ़ शिक्षण केंद्रों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपकर यह जानकारियां किसानों तक पहुंचाई जाए तथा किसानों की जिज्ञासाएं एवं समस्याएं संबद्ध पक्षों तक तत्काल पहुंचाई जाए। भारतीय किसान को इसकी जानकारी नहीं है कि उसे क्या–क्या सुविधाएं, कहां–कहां से और किन शर्तों पर उपलब्ध हो रही है? अतः इन सुविधाओं का बड़ा भाग बिचौलिए वह तथाकथित किसान हड़प लेते हैं या वे अवशोषित रह जाती है। जो सुविधाएं किसानों तक पहुंच पाती है उनका भी उनके बीच समुचित आवंटन नहीं हो पाता। इनके आवंटन में स्थानीय, संकीर्ण, दूषित दलगत राजनीति हावी रहती है। किसानों को इनकी सामयिक जानकारी एवं वितरण की स्थाई संस्थागत व्यवस्था की जाए। पानी एवं ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों का विकास किया जाए एवं इनका राष्ट्रीय ग्रिड बनाकर कृषि को इन दोनों की आवश्यकता अनुसार एवं नियमित पूर्ति की जाए। रेल बजट की भांति विशुद्ध रूप से देश का पृथक कृषि बजट बनाया जाए और प्राथमिकताओं का स्पष्ट निर्धारण किया जाए। फसलों के समर्थित मूल्यों का निर्धारण लागत के आधार पर किया जाए तथा किसानों को न्यूनतम कीमत की गारंटी दी जाए। कृषि उत्पादों के भंडारण की क्षमता को इस प्रकार बढ़ाया जाए कि किसान को बाजार कीमतों का लाभ मिल सके। सारे देश में फसल बीमा योजना अविलंब लागू की जाए और प्रस्तावित कृषि राहत कोष की स्थापना अविलंब की जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- ❖ बसंत ओधे, शांति विजय जैन, राजस्थान में कृषि उत्पादन
- ❖ डॉक्टर कृष्णकांत व्यास, डॉक्टर सुखपाल भंडारी, मुद्रा विज्ञान
- ❖ डॉक्टर एन एल अग्रवाल, भारतीय कृषि का अर्थ तंत्र
- ❖ रुद्रदत्त के पीएम सुंदरम, भारतीय अर्थव्यवस्था
- ❖ एल. एन. गुप्ता कोमा राजस्थान में कृषि विकास 6 मेहता, मदन लाल के और मुखर्जी एन., सिंचाई और नाइट्रोजन का संतुलन।

♦❐♦